

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

(665)

क्रमांक प.३(184)नवीनि/ ३/ २०१२

जयपुर, दिनांक

आदेश

17 APR 2013

"प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" के लिए विभाग के आदेश क्रमांक प.३(54)नवीनि/ ३/ २०११ दिनांक 17.10.2012 से जारी किये गये दिशा-निर्देशों में विन्दु संख्या 21 के अनुसार ग्राम/प्राधिकरण व नगरालिकाओं के मारठर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवरिधि ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम से वर्तमान आवादी क्षेत्र की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों की आवादी क्षेत्र से 200 मीटर तक की परिधि में आवादी विस्तार के लिए आवादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर पट्टा देने की अधिकारिता दी गई थी। एवं इस प्रयोजन हेतु पंचायतों को संबंधित प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलक्टर द्वारा पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश क्रमांक प.३(192)नवीनि/ ३/ २०१० दिनांक 4.1.2013 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है।

ऐसी भूमि जो परिधीय क्षेत्र में भी आती है लेकिन ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम की आवादी के 500 मीटर की परिधि एवं अन्य ग्राम की आवादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है और उस पर आवास/आवादी बनी हुई है, उनका नियमन किसके द्वारा किया जावेगा, इस विषय में नगरीय निकायों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः इस विषय में स्पष्ट किया जाता है कि परिधीय क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम की आवादी के 500 मीटर की परिधि एवं अन्य ग्राम की आवादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर के क्षेत्र में बने हुए आवासों/मकानों का नियमन सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा किया जावेगा।

राज्यपक्ष की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वातंत्र्य विभाग।
- निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वातंत्र्य विभाग।
- उप सचिव मुख्य सचिव महोदय, राज्यो जयपुर।
- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण निकास एवं पंचायतीराज विभाग/नगरीय विकास, आवासन एवं स्वातंत्र्य शासन विभाग, राज्यो जयपुर।
- निजी सचिव प्रापुर शासन सचिव, राजस्थान विभाग, राज्यो जयपुर।
- रामरत शासनीय आयुक्त, राजरथान।
- आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
- समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
- संयुक्त शासन सचिव(हितीय/तृतीय)/उप शासन राजिव(प्रथम), नगरीय विकास विभाग।
- मिरेश, राजनीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित निर्देशान्वार लेख है कि उपरोक्त सामर्त सम्बन्धित को प्रेषित कराने का श्रम करें।
- सचिव, नगर निकास न्याय (रामरत)
- राजित प्रापुरी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वेषीय

(394)